जनसत्ता

आरक्षण की भूख

राजस्थान में एक बार फिर गुर्जर समुदाय पांच फीसद आरक्षण की मांग लेकर सड़कों पर उतर आया है। रेल की पटरियों पर तंबू गाड़ दिया है। जिस रेल पटरी पर उन्होंने बसेरा डाल रखा है, वह देश की व्यस्ततम रेल लाइन है। इस तरह बहुत सारी गाड़ियों का रास्ता बदलना पड़ा है और कई गाड़ियां रोक दी गई हैं। पिछले तेरह सालों में यह छठा आंदोलन है, जब राज्य सरकार को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब तक भाजपा सरकार को चार बार और कांग्रेस को दो बार गुर्जर आरक्षण आंदोलन का सामना करना पड़ा है। हालांकि राजस्थान सरकार ने आंदोलनकारियों से बातचीत की कोशिश की, पर कामयाबी नहीं मिल पाई। पुलिस ने रेल लाइन खुलवाने का प्रयास किया, जिसके चलते आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़पें भी हुईं। इसके पहले भी करीब बारह साल पहले जब यह आंदोलन हिंसक हुआ था, तब करीब तीस लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान हुआ था। इसलिए सरकार की कोशिश है कि आंदोलन हिंसक रूप न लेने पाए, पर गुर्जर नेता इस बात पर अड़े हैं कि इस बार वे आरक्षण लेकर ही धरने से उठेंगे। पर मुश्किल यह है कि राज्य सरकार के लिए आरक्षण की मांग पूरी कर पाना संभव नहीं है।

पहली बार जब गुर्जर आंदोलन शुरू हुआ था, तब तत्कालीन भाजपा सरकार ने पांच फीसद आरक्षण की मांग मान ली थी, पर वह मामला अदालत में जाकर निरस्त हो गया था। क्योंकि कानूनी रूप से आरक्षण की सीमा को पचास फीसद से ऊपर नहीं रखा जा सकता। फिर जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी तब भी आंदोलन उठा और उसने मांग मान ली, पर अदालत ने फिर उस पर रोक लगा दी। हालांकि उस समय गुर्जर समुदाय को एक फीसद का आरक्षण मिल गया। अब जब केंद्र सरकार ने सामान्य वर्ग के लिए दस फीसद आरक्षण का प्रावधान किया है, तब गुर्जर समुदाय ने अपनी मांग फिर से उठा दी है कि उन्हें बाकी का चार फीसद आरक्षण भी मिले। अब राज्य सरकार इस मसले को केंद्र के पाले में डाल रही है कि चूंकि यह मामला संविधान संशोधन का है, इसलिए वही इस मांग को पूरा करने की दिशा में कुछ कर सकती है। मगर केंद्र के लिए भी ऐसा करना संभव नहीं है। लिहाजा, इस आंदोलन का नतीजा कुछ निकलने वाला नहीं है।

दरअसल, राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए विभिन्न राज्यों में कृषक समुदाय के लोगों को आरक्षण देने का लालच देते रहे हैं। इसी का नतीजा है कि हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन शुरू हुआ, गुजरात में पटेल आंदोलन पर उतरे, महाराष्ट्र में मराठा और राजस्थान में गुर्जर। ये सभी जातियां सामाजिक रूप से सबल मानी जाती हैं। सारे राजनीतिक दलों को पता है कि आरक्षण की सीमा को पचास फीसद से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। संविधान में जिन समुदायों को आरक्षण मिला हुआ है, उसे कम करके दूसरे समुदायों के लोगों को उसमें हिस्सा नहीं दिया जा सकता। फिर भी जब उन्हें अपना जनाधार बढ़ाना होता है, चुनावों के समय आरक्षण का मुद्दा छेड़ देते हैं। इस तरह आरक्षण का उद्देश्य प्रश्नांकित होता रहता है। विचित्र है कि आरक्षण की मांग करने वाले भी जानते हैं कि संविधान के तहत उनकी मांगों को पूरा करना किसी सरकार के लिए संभव नहीं है, फिर भी वे आंदोलन पर उतर आते हैं।

शराब का कहर

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जहरीली शराब ने फिर कहर बरपाया है। सहारनपुर, शामली, कुशीनगर, हरिद्वार, रुड़की सहित कई जगहों पर जहरीली शराब पीने से बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं। अस्पतालों में इलाज करा रहे पीड़ितों की तादाद तो और भी ज्यादा है। सबसे ज्यादा मौतें हरिद्वार और इससे सटे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में हुई हैं। यह घटना बताती है कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। जाहिर है, ये राज्य शराब माफिया की गिरफ्त में हैं। स्थानीय प्रशासन और पुलिस तो आंखें मूंदे हुए हैं और किसी पर भी कार्रवाई कर पाने में लाचार है। हमेशा से होता यही आया है कि जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं तो फौरी और रस्मी तौर पर कुछ अधिकारी-कर्मचारी निलंबित किए जाते हैं और मृतकों के परिजनों को मुआवजा देकर पिंड छुड़ा लिया जाता है, लेकिन ऐसी कार्रवाई किसी पर नहीं होती, जिससे कोई सबक ले सके। वही अब भी हुआ है।

जहरीली शराब का कारोबार करने वालों का जाल काफी बड़ा है। जिस तरह यह धंधा चलता आ रहा है उससे तो लगता है कि यह व्यवस्था का हिस्सा बन गया है। और जहरीली शराब ही क्यों, इस तरह के कई अवैध कारोबार होते हैं जिनके बारे में सरकारें, प्रशासन और पुलिस सब जानते हैं, लेकिन उन पर लगाम नहीं लगाते। यह कोई छिपी बात नहीं है कि अवैध शराब का धंधा स्थानीय प्रशासन और पुलिस की मिलीभगत से ही चल पाता है। कच्ची शराब का सेवन आमतौर पर निचले तबके के लोग करते हैं, क्योंकि यह सस्ती होती है और आसानी से मिल जाती है। इसलिए निम्न-वर्गीय बस्तियों, झुग्गी बस्तियों में कच्ची शराब के मटके ज्यादा चलते हैं। पाउचों तक में शराब बिकती है। ग्रामीण इलाकों में कच्ची शराब का कारोबार बड़े पैमाने पर चलता है। पर पुलिस और प्रशासन इन्हें इसलिए चलने देता है, क्योंकि ये धंधे उगाही के बड़े स्रोत होते हैं। जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो उसे रफा-दफा कर दिया जाता है और थोड़े दिन बाद फिर से धंधा शुरू हो जाता है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन कठघरे में आएगा ही।

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जहरीली शराब से हुई मौतें बता रही हैं कि इन राज्यों की सरकारों ने सत्ता में आने के बाद शराब माफिया पर डंडा चलाने की हिम्मत नहीं दिखाई, बल्कि शराब माफिया के सामने हाथ खड़े कर दिए। अगर शराब माफिया के खिलाफ अभियान चलता तो लोग मारे जाने से बच सकते थे। शराब की बिक्री राज्य सरकारों के लिए राजस्व का बड़ा स्रोत होती है, लेकिन अवैध शराब का कारोबार करने वालों से जो उगाही होती है, वह भी मामूली नहीं होती। इसलिए चाहे किसी पार्टी की सरकार सत्ता में रहे, शराब माफिया पर इसका कोई असर नहीं पड़ता और इसीलिए अवैध शराब के धंधे पर लगाम नहीं लग पाती। यह कोई पहला मौका नहीं है जब जहरीली शराब के कारण इतनी मौतों की खबर आई हो। चार साल पहले लखनऊ के मलिहाबाद में जहरीली शराब से पैंतीस से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन शर्म की बात तो यह है कि ऐसे बड़े हादसों के बाद भी सरकार की आंखें नहीं खुलतीं। पिछली घटनाओं से भी कोई सबक नहीं लिया जाता। अगर सरकार ठान ले तो जहरीली शराब बेचने वालों का सफाया करना कोई मुश्किल काम नहीं है!

कल्पमेधा

प्रगतिशील समाज, संगठनों की उपयोगिता से आगे निकल जाता है, ठीक उसी प्रकार जैसे बच्चों की पोशाकें छोटी पड़ जाती हैं।
-हेनरी जॉर्ज

राजकोषीय घाटे का संकट

जयंतीलाल भंडारी

वित्त वर्ष 2018-19 के बजट में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 6.24 लाख करोड़ रुपए रखा गया था, जो दिसंबर 2018 के अंत तक 7.01 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो बजट अनुमान से करीब 12.4 फीसद ज्यादा है। स्पष्ट है कि चालू वित्त वर्ष 2018-19 के पिछले नौ महीनों में जो राजकोषीय घाटा ऊंचाई पर पहुंच गया है उसे पाटा जाना मुश्किल है।

पिछले हफ्ते एक वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि भारत सरकार के 2019-20 के अंतरिम बजट में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 3.4 फीसद रखे जाने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसे हासिल करने में सरकार को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। रेटिंग एजेंसी ने यह भी कहा कि अंतरिम बजट में खर्च बढ़ाने के कदम उठाए गए हैं। हालांकि बजट में राजस्व बढ़ाने के पर्याप्त उपाय नहीं किए गए हैं, लेकिन फिर भी निश्चित रूप से अंतरिम बजट की घोषणाओं से विकास को बल मिलेगा। नया अंतरिम बजट राजकोषीय घाटे को कम करने के लिहाज से ठीक नहीं है। सरकार ने इससे पहले, राजकोषीय घाटे को मार्च 2020 तक जीडीपी के 3.1 फीसद तक और मार्च 2021 तक तीन फीसद तक सीमित रखने की प्रतिबद्धता जताई थी। एक रेटिंग एजेंसी ने कहा कि अगले वित्त वर्ष 2019-20 में राजकोषीय घाटा (जीडीपी) का 3.6 फीसद रहेगा।

गौरतलब है कि विभिन्न रेटिंग एजेंसियों की तरह देश और दुनिया के कर विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों ने भी राजकोषीय घाटे के घोषित लक्ष्य को चुनौतीपूर्ण बताया है। लेकिन यह भी कहा है कि अनुकूल आर्थिक परिवेश में सरकार अपना अंतरिम बजट प्रस्तुत करते समय पूर्ण स्वायत्तता का उपयोग करते हुए बजट को सभी के लिए हितप्रद बनाते हुए भी दिखाई दी। इससे अर्थव्यवस्था के साथ-साथ विभिन्न वर्गों को लाभ मिलेगा। नया अंतरिम बजट प्रमुखतया खेती और किसानों को लाभान्वित करते हुए दिखाई दे रहा है। सरकार ने इस बजट में नकद के रूप में राहत देने के लिए ऐसी योजना प्रस्तुत की है जिसके तहत किसानों का आर्थिक बोझ कम करने के लिए उनके खातों में नकद रकम हस्तांतरित की जाएगी। कृषि कर्ज का लक्ष्य बढ़ाया गया है। नए बजट में सरकार ने दो हेक्टेयर जमीन वाले किसानों को छह हजार रुपए सालाना देने का एलान किया, जो उनके खाते में सीधे जमा हो जाएगा। सरकार यह रकम तीन किस्तों में देगी। इससे बारह करोड़ किसानों को सीधा लाभ होगा।

नया बजट राजकोषीय घाटे का है। लेकिन मध्यम वर्ग को जो सौगातें दी गई हैं, उससे बचत और निवेश में वृद्धि होगी। सरकार ने बजट में आयकर छूट की सीमा को ऐतिहासिक रूप से बढ़ाया है। कर छूट की सीमा ढाई लाख रुपए से बढ़ा कर पांच लाख रुपए कर दी है। इससे तीन करोड़ छोटे आयकरदाताओं को फायदा होगा। निवेश करने पर साढ़े छह लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं लगेगा। सावधि जमा पर चालीस हजार रुपए तक के ब्याज पर कर नहीं देना होगा। मानक छूट चालीस हजार रुपए से बढ़ा कर पचास हजार रुपए की गई है। तेजी से बढ़ रही भारतीय अर्थव्यवस्था का लाभ कामगारों और विभिन्न सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को देने के लिए बजट में प्रावधान बढ़ाए गए हैं। कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी भुगतान सीमा दस लाख रुपए से बढ़ा कर बीस लाख रुपए की गई है। मजदूरों का बोनस सात हजार रुपए किया गया है। नए बजट के तहत ईपीएफओ की बीमा राशि छह लाख रुपए की गई है। इससे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की मौत पर छह लाख रुपए का मुआवजा सुनिश्चित किया गया है। 60 साल की उम्र के बाद तीन हजार रुपए की पेंशन, 15 हजार वेतन वाले मजदूरों के लिए पेंशन और सौ रुपए महीने के अंशदान पर बोनस की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है।

नए अंतरिम बजट के तहत रियल एस्टेट को प्रोत्साहन दिखाई दिया है। स्टार्टअप के लिए नई सुविधाएं दी गई हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, छोटे उद्योग-कारोबार और कौशल विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए बजट आबंटन बढ़ाया गया है। उज्ज्वला योजना के तहत दो करोड़ और मुफ्त गैस कनेक्शन के प्रावधान हैं। ऐसे विभिन्न प्रावधानों से आम आदमी की क्रय शक्ति बढ़ेगी और उद्योग-कारोबार को गतिशीलता मिलेगी।

चूंकि 2019-20 का अंतरिम बजट आम चुनाव के पहले का आखिरी बजट था, अतएव इसे लोकलुभावन बनाया गया है। निश्चित रूप से इस बजट को लोकलुभावन बनाने के लिए सरकार राजकोषीय घाटे संबंधी कठोरता से कुछ पीछे हटी है। आगामी वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3.4 फीसद तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है। चालू वित्त वर्ष के राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3.3 फीसद तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन यह भी तय लक्ष्य से ज्यादा होता दिखाई दे रहा है। वित्त वर्ष 2018-19 के बजट में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 6.24 लाख करोड़ रुपए रखा गया था, जो दिसंबर 2018 के अंत तक 7.01 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो बजट अनुमान से करीब 12.4 फीसद ज्यादा है। स्पष्ट है कि चालू वित्त वर्ष 2018-19 के पिछले नौ महीनों में जो राजकोषीय घाटा ऊंचाई पर पहुंच गया है उसे पाटा जाना मुश्किल है।

उल्लेखनीय है कि चालू वित्त वर्ष के दिसंबर माह तक यानी पहले नौ महीनों में जहां प्रत्यक्ष कर संग्रह में साढ़े चौदह फीसद की बढ़ोतरी हुई है, वहीं अप्रत्यक्ष कर संग्रह पिछले साल के बराबर बना हुआ है। व्यय की तुलना में राजस्व पर दबाव ज्यादा दिख रहा है। प्रत्यक्ष कर के तहत कॉरपोरेट कर संग्रह चौदह फीसद बढ़ कर दिसंबर के अंत तक 4.27 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले साल की समान अवधि में हुए 3.75 लाख करोड़ रुपए की तुलना में ज्यादा है। वहीं आयकर संग्रह में 15.2 फीसद की बढ़ोतरी हुई है और यह पिछले साल के 2.62 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 3.02 लाख करोड़ रुपए हो गया है। दिसंबर के अंत तक केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) संग्रह 3.4 लाख करोड़ रुपए रहा है। जनवरी तक कुल संग्रह 3.76 लाख करोड़ रुपए रहा। इससे पता चलता है कि फरवरी और मार्च 2019 में सीएसजीटी संग्रह से 1.28 लाख करोड़ रुपए की वसूली की जरूरत है, जिससे 5.04 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य पूरा हो सके। गैर कर राजस्व बजट के लक्ष्य का साठ फीसद हुआ है। दिसंबर के अंत तक विनिवेश प्रक्रिया से 34215 करोड़ रुपए आए, जबकि लक्ष्य अस्सी हजार करोड़ रुपए का रखा गया है।

इसमें कोई दो मत नहीं कि चालू वित्त वर्ष में सरकार वैश्विक आर्थिक घटनाक्रम के कारण देश के राजकोषीय घाटे की बढ़ती चिंताओं को समझ रही है। इसीलिए कमजोर हुए रुपए की वजह से सरकार लगातार अपने जमा और खर्च की समीक्षा करती रही है। इस दौरान कई कम जरूरी खर्चों पर नियंत्रण किया गया और कई क्षेत्रों में आमदनी बढ़ाने का भी प्रयास हुआ। अब सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष में यानी फरवरी और मार्च 2019 में होने वाले गैरजरूरी खर्चों पर लगाम लगाने की रणनीति भी बनाई है। मौजूदा वित्त वर्ष में सरकार अपना उधारी कार्यक्रम पहले ही सत्तर हजार करोड़ रुपए घटा कर 6.05 लाख करोड़ रुपए कर चुकी है।

आगामी वित्त वर्ष में आमदनी की तुलना में खर्च तुलनात्मक रूप से अधिक होंगे, क्योंकि विभिन्न उम्मीदों और वादों को पूरा करने के लिए अधिक धन की जरूरत होगी। लेकिन तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए राजकोषीय घाटे के आकार में कुछ वृद्धि उपयुक्त ही कही जा सकती है। ऐसे सीमित राजकोषीय घाटे से एक ओर आम आदमी की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे नई मांग का निर्माण होगा, उद्योग-कारोबार की गतिशीलता बढ़ेगी और बढ़े हुए सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक निवेश से बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। लेकिन यह अत्यंत जरूरी है कि सरकार राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के शुरू से ही रणनीति के साथ आगे बढ़े। यदि सरकार राजकोषीय घाटे को लक्ष्य के अनुरूप जीडीपी के 3.4 फीसद के स्तर पर बनाए रखने में सफल होगी, तो यह सरकार की बड़ी उपलब्धि होगी।

बचपन और मासूमियत

सूर्यप्रकाश चतुर्वेदी

ठीक ही कहा जाता है कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं। मासूमियत, पवित्रता, सच्चाई और राग-द्वेष से परे साफ-सुथरा जीवन कहीं देखना हो तो बच्चों में ही मिल सकता है। अंगरेजी के प्रकृति प्रेमी कवि वड्र्सवर्थ का विचार है कि बच्चा ही ईश्वर के सबसे करीब होता है और यही कारण है कि वह जन्म लेने पर स्वर्ग की मधुर स्मृतियों को याद करते हुए रोता है। वहां जो छूट गया उसकी याद उसे द्रवित करती हैं और भौतिक जीवन के समस्त आकर्षण ईश्वर की करीबी से दूर आ जाने की भरपाई नहीं कर पाते। उन्हें बनाते भी बड़े ही हैं और बिगाड़ते भी बड़े ही हैं। जैसे-जैसे वह बड़ा होता जाता है, लोगों के संपर्क में आता जाता है और जिस किसी के भी संपर्क में आता है उससे वह कुछ न कुछ सीखता है। शुरुआत घर से ही होती है और फिर आसपास के लोग, शहर और धीरे-धीरे यह सामाजिक दायरा बढ़ता जाता है।

बच्चा चूंकि जिज्ञासु होता है, अतः वह हरेक से कुछ न कुछ सीखता ही है फिर भले ही वह अच्छाई हो या फिर बुराई। समाज के संपर्क में आते-आते उसकी मासूमियत, सहजता, पवित्रता व जन्मजात सहृदयता समाप्त होती जाती है। उसका स्थान वे सारी चीजें लेती जाती हैं जिन्हें हम भौतिक सफलता के लिए जरूरी मानते हैं। इसी में क्रूरता, कुटिलता, जालसाजी, चालाकी, फरेब भी हैं और सफलता के लिए किसी भी हद तक जाने की जिद व कुछ भी कर गुजरने का जज्बा भी। माकूल परिवेश, वातावरण और परिस्थितियां मिलने पर सहानुभूति, सद्भाव, ईमानदारी, सही काम करने का साहस और त्याग की भावना भी अंकुरित होती है। पर ये भाव अपवाद स्वरूप भी जाग्रत होते हैं। तभी तो जॉर्ज बनार्ड शॉ ने स्कूल कॉलेज से पढ़ कर निकलने वालों को 'स्कूल मेड मास्टर्स' कहा था, यानी वहां से पढ़-लिख कर अच्छे विद्यार्थी व नागरिक नहीं, बल्कि शैतान निकलते हैं। बेशक यह उनकी अपनी शैली में आधुनिक चमक दमक पर टिप्पणी थी।

दुनिया मेरे आगे

दो घटनाएं हैं करीब पच्चीस साल पुरानी। पंजाब व मध्य प्रदेश के बीच सोलह साल के लड़कों का मैच हो रहा था और दोनों ही टीमें खुल कर पूरी खेल भावना से खेल रही थीं। तभी देखा कि पंजाब के कोच बाउंड्री लाइन पर गए और वहां तैनात खिलाड़ी के द्वारा कप्तान को संदेश भेजने लगे। उनकी हिदायत के बाद कप्तान ने लेग स्टंप पर अटैक करना शुरू किया व वहां खास क्षेत्ररक्षक भी तैनात किए व शॉर्ट पिच गेंदें आनी शुरू हुईं। सारा खेल बदल गया। यानी कोच व उस्ताद लोग ही दांव-पेच सिखा कर अपना स्वाभाविक और नैसर्गिक क्रिकेट खेल रहे बच्चों का खेल बिगाड़ कर उसे हार-जीत प्रधान बना देते हैं और अच्छा खासा खेल पेशेवर राजनीति का शिकार हो जाता है।

दूसरी घटना कानून-व्यवस्था व न्याय से जुड़ी पुलिस से संबंधित है। हुआ यूं कि तब करीब बारह वर्ष की उम्र के मेरे बेटे के पासपोर्ट के फॉर्म की जांच-पड़ताल के लिए पुलिस थाने से फोन आया। वह स्कूल से लौटा और अपने मित्र के साथ थाने पहुंचा। वहां उससे कहा गया कि वह सौ रुपए दे क्योंकि कागज, पेन व फॉर्म भरने में खर्च तो आता ही है। उसे नहीं पता था और सौभाग्य से उसके पास सौ रुपए थे तो उसने दे दिए। वह घर लौटा और उसने जब यह बताया कि थाने पर उससे रिश्वत ली गई है। तब उसे पहली बार पता चला था कि रिश्वत क्या होती है। जिन सामाजिक बुराइयों के बारे में बच्चे जानते तक नहीं, उनके बारे में ऐसे नकारा लोग ही उन्हें बताते हैं। झूठ, फरेब, मक्कारी, जालसाजी के बारे में वे बड़ों से ही सीखते हैं और जब से मोबाइल और वह भी स्मार्ट फोन का चलन बढ़ा है, झूठ व झांसेबाजी की घटनाएं भी बढ़ी हैं।

बच्चे घर में व आसपास जैसा वातावरण, व्यवहार, बातचीत, तौर-तरीके व संस्कार देखते हैं, वही वे अपनाते लगते हैं। यदि वे लोगों को प्यार, दोस्ती, परस्पर सम्मान, दया, त्याग, सच, ईमानदारी व मेहनत करते हुए देखेंगे तो इन्हीं गुणों को अपनाएंगे और यदि बेईमानी, झूठ, फरेब, झांसेबाजी, गाली-गलौज, लड़ाई-झगड़े व नफरत के माहौल में बड़े होंगे तो वे भी इन दुगुर्णों के शिकार होंगे। यह जिम्मेदारी बड़ों की है कि वे उन्हें अच्छा व साफ-सुथरा व स्वस्थ वातावरण दें। उन्हें बनाते भी बड़े हैं और बिगाड़ते भी वे ही हैं। बच्चों को अपनी नैसर्गिक व जन्मजात मासूमियत, पवित्रता और शुचिता के साथ खुले वातावरण में बिना अनावश्यक रोक-टोक व दबाव तथा डर के किलक कर बड़ा होने दीजिए। दुनियादारी के दाव पेंचों से उन्हें दूर ही रखिए। बचपन निर्बाध बहती हुई पवित्र नदी के सदृश है। उसे निरर्थक बंधनों व बाधा से रोक कर प्रदूषित न करें।

नशे की गिरफ्त में

वैसे तो नशा पूरे भारत में एक समस्या है, लेकिन पंजाबी नौजवानों में नशे की बढ़ती प्रवृति ने पूरे पंजाब को खतरे में डाल दिया है। पंजाब के ज्यादातर कॉलेजों और स्कूलों में नशे की लत बढ़ती जा रही है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पंजाब में हर साल साढ़े सात हजार करोड़ के नशीले पदार्थों का सेवन किया जाता है। इनमें से अकेले साढ़े छह हजार रुपए की हेरोइन की खपत होती है। पंजाब में पहुंचने वाली सारी हेरोइन के आने का एक ही जरिया है, और वह है पाकिस्तान। इस रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब दो लाख से ज्यादा लोग नशीले पदार्थों के आदी हैं। इनमें से करीब सवा लाख हेरोइन के नशेड़ी हैं, जबकि पंजाब में ड्रग्स का सेवन करने वालों की संख्या करीब नौ लाख है। रिपोर्ट के मुताबिक, पंजाब में हर दिन ड्रग्स के आदी लोग अपने नशे की खुराक के लिए करीब बीस करोड़ रुपए खर्च करते हैं, जबकि हेरोइन का आदी व्यक्ति करीब चौदह सौ रुपए रोजाना तक खर्च कर देता है। नशीली दवाओं का सेवन करने वालों में 76 फीसद 18 से 35 की उम्र के हैं। नशे की समस्या ने राज्य के भविष्य को भी अंधकारमय बना दिया है। नशे की इस लत को खत्म करने में समाज के नागरिक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

● *विक्रमजीत सिंह, बठिंडा*

जहरीली शराब से मौतें

कई बार देखने में आया है कि जहरीली शराब से देश में कभी यहां तो कभी वहां मौते होती रहती हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर और सहारनपुर में जहरीली शराब से कई लोग मारे गए। सरकार ने कदम उठाते हुए संबंधित विभाग के अफसरों और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। अब जांच होगी, सजा होगी या फिर लापरवाह कर्मचारी व अफसर छूट भी सकते हैं। पर उन गरीबों का क्या होगा जिनके घर उजड़ गए हैं? सवाल है कि आखिर ऐसे हादसे होते क्यों हैं? देश में ऊपर से लेकर निचले स्तर तक सरकारी विभागों में बढ़ता भ्रष्टाचार भी इन मौतों के लिए जिम्मेदार है।

● *महेश नेनावा, इंदौर*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

सेहत की सवारी

आपके समाचार पत्र में 24 जनवरी को 'साइकिल की सवारी' लेख छपा। यह बहुत ही सार्थक लेख है। भारत के मध्य और उच्च वर्ग में बीते जमाने की सवारी समझी जाने वाली साइकिल को अब भारत में निकृष्ट दृष्टि से देखने की एक आदत सी बन गई है, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधानों से अब यह सिद्ध हो चुका है कि प्रतिदिन अपने सामान्य काम साइकिल से करने वाले लोग मोटरसाइकिल, स्कूटर या कारों का प्रयोग करने वालों से हर तरह से स्वस्थ और लंबा जीवन जीने वाले होते हैं। यूरोप के कई देशों के लोग और एशिया में चीन के लोग अपने-अपने देश में पर्यावरण, प्रकृति और अपने स्वास्थ्य के प्रति हम भारतीयों से ज्यादा सचेत और जागरूक हैं। वे अपना दैनिक और सामान्य काम जैसे बाजार और दफ्तर भी जाने का काम बिना संकोच के करते हैं। उनके बच्चे अक्सर स्कूल-कॉलेज जाने में भी साइकिल का ही प्रयोग करते हैं। वैज्ञानिक शोधों से यह सिद्ध हो चुका है कि साइकिल चलाने से साल भर में पांच किलो तक वजन कम करके बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है। शहरों में साइकिलों का प्रयोग बढ़ने से काफी हद तक प्रदूषण से भी मुक्ति मिल सकती है। प्रदूषण से होने वाले रोगों से भी छुटकारा मिलता है।
हमें अपने देशहित में साइकिल का प्रयोग अधिकाधिक करना चाहिए।

● *निर्मल कुमार शर्मा, गाजियाबाद*

महिला सशक्तिकरण

हर ओर महिला सशक्तिकरण की बात तो हो रही है, लेकिन क्या वाकई महिलाएं सशक्त हुई हैं, यह कहना मुश्किल है। समाचार पत्र हों या टीवी चैनल सभी बलात्कार, दहेज और भ्रूण हत्या की घटनाओं से भरे मिलते हैं। दुर्भाग्य तो यह है कि इन आंकड़ों में दिन-प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा और शोषण की घटनाएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। तमाम झंझावतों को पार करते हुए भी महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का प्रयास कर रही हैं। कई क्षेत्रों में महिलाएं पुरुषों से आगे हैं, लेकिन बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पुरुष प्रधान मानसिकता वाले लोग हैं, वहां महिलाओं को संघर्ष करना पड़ रहा है। इसी मानसिकता की वजह से हमारा देश बाकी देशों से पीछे है। अगर देश को आगे बढ़ाना है तो महिलाओं को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी है। स्त्री और पुरुष गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर कोई एक पहिया भी खराब हो गया तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। हमें अपनी हर बेटी को इतना सशक्त बनाना है कि उनके आगे आने वाली हर चुनौती को वो पार सकें। तभी सही मायने में महिला सशक्तीकरण हो पाएगा।

● *मोहम्मद अनस, दिल्ली विवि*

खस्ताहाल पटरियां

रोजाना लाखों लोग अपनी यात्रा के लिए रेलगाड़ी पर निर्भर हैं। इसलिए 2019 के बजट में रेलगाड़ियों के लिए अच्छा खासा बजट तैयार किया गया है। बजट के साथ यह दावा भी किया गया कि ज्यादातर रेल लाइनों का सुधार कार्य पूरा हो चुका है और इनका तेजी से विस्तार भी हो रहा है। लेकिन तीन फरवरी को हुआ सीमांचल एक्सप्रेस का रेल हादसा इस वादे की असलियत को बयां करता दिख रहा है। यह बीते दस महीनों में हुआ पाचवां बड़ा हादसा है, जिसमें आर्थिक नुकसान के साथ-साथ लोगों को अपनी जाने भी गंवानी पड़ीं। पिछले चार सालों में रेल दुर्घटना की संख्या सबसे ज्यादा रही है। ज्यादातर हादसों का कारण रेल पटरियों की खस्ता हालत को बताया जा रहा है। यह बात तो साफ है कि वादों और बातों से इन पटरियों को ठीक नहीं किया जा सकता। सरकार जल्द से जल्द रेल पटरियों की खस्ता हालत को दुरुस्त करवाए। साथ ही ऐसे कर्मचारियों को सजा भी दी जाए जो अपने काम को जिम्मेदारी के साथ करना नहीं जानते।

● *निशांत रावत, दिल्ली विवि*